



Lakshya IAS

academy

14
OCT
2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



लक्ष्य IAS तेलीबाग लखनऊ



Lakshya IAS Academy



8182093320



1. पीएम गतिशक्ति ने भारत की एकीकृत अवसंरचना योजना में परिवर्तन के पाँच वर्ष पूरे किए

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पूरे भारत में एकीकृत अवसंरचना योजना और बहुविध संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। यह संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो अवसंरचना और भू-स्थानिक आँकड़ों को एक साझा जीआईएस-आधारित मंच पर लाता है। यह ढाँचा सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, जलमार्गों, हवाई अड्डों, जन परिवहन और रसद अवसंरचना को जोड़ता है, जिससे समन्वित परियोजना योजना संभव होती है। यह अवसंरचना संबंधी कमियों की पहचान करने, अंतिम छोर तक संपर्क में सुधार करने, देरी कम करने और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में सहायता करता है। 2026 तक, 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत राष्ट्रव्यापी अवसंरचना योजना मंच से जोड़ा जा चुका था।



1. PM GatiShakti Completes Five Years of Transforming India's Integrated Infrastructure Planning

PM GatiShakti National Master Plan was launched on 13 October 2021 to promote integrated infrastructure planning and multimodal connectivity across India. It follows a whole-of-government approach, bringing infrastructure and geospatial data onto a common GIS-based platform. The framework connects roads, railways, ports, waterways, airports, mass transport and logistics infrastructure, enabling coordinated project planning. It helps identify infrastructure gaps, improve last-mile connectivity, reduce delays and optimise resources. By 2026, 58 Central Ministries and Departments and all 36 States and Union Territories had been onboarded onto the integrated nationwide infrastructure planning platform.



मुख्य बिंदु:

- एकीकरण के पाँच वर्ष: 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति समन्वित, आँकड़ा-आधारित अवसंरचना योजना के लिए एक राष्ट्रव्यापी ढाँचे के रूप में विकसित हुआ है।
- राष्ट्रव्यापी संस्थागत कवरेज: जीआईएस-आधारित मंच अब समन्वित योजना के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को एकीकृत करता है।

Key Points:

- Five Years of Integration: Launched on 13 October 2021, PM GatiShakti has developed into a nationwide framework for coordinated, data-driven infrastructure planning.
- Nationwide Institutional Coverage: The GIS-based platform now integrates 58 Central Ministries and Departments alongside all 36 States and Union Territories for coordinated planning.

- एकीकृत अवसंरचना योजना: यह मंच परियोजना समन्वय और दक्षता में सुधार के लिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, जलमार्गों, उपयोगिता सेवाओं और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित जानकारी को एकीकृत करता है

2. सरकार ने भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भिक्षा वृत्ति मुक्त दिल्ली पहल को तेज किया

- ✎ भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत पहल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सहायता योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। इसका भिक्षावृत्ति घटक पहचान, लामबंदी, बचाव, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका सहायता के माध्यम से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उन्हें सार्वजनिक स्थानों से हटाने के बजाय समाज की मुख्यधारा में उनका सम्मानजनक पुनःएकीकरण करना है। कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम और देशभर की अन्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ शामिल हैं।



मुख्य बिंदु:

- दिल्ली पुनर्वास अभियान मजबूत हुआ: केंद्र और दिल्ली सरकार भिक्षा वृत्ति मुक्त दिल्ली पहल के अंतर्गत समन्वित पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण उपायों को आगे बढ़ा रही हैं।
- योजना का दायरा देशभर में बढ़ा: भिक्षावृत्ति योजना 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 216 शहरों में संचालित है, जो व्यापक पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में सहायता करती है।
- देशभर में सौ शहर लक्षित: सरकार का लक्ष्य मापनीय संकेतकों, डिजिटल निगरानी और समन्वित पुनर्वास उपायों के माध्यम से 2031 तक 100 शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है।

2. Government Steps Up Bhiksha Vritti Mukt Delhi Initiative to Advance Goal of a Begging-Free India

- ✎ The Bhiksha Vritti Mukt Bharat initiative is being implemented under the SMILE scheme, or Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise, by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Its beggary component focuses on comprehensive rehabilitation of persons engaged in begging through identification, mobilisation, rescue, shelter, healthcare, counselling, education, skill development and livelihood support. The programme seeks their dignified reintegration into mainstream society rather than merely removing them from public spaces. Implementation involves Central and State governments, Union Territories, urban local bodies, municipal corporations and other implementing agencies nationwide.



Key Points:

- Delhi Rehabilitation Drive Strengthened: The Centre and Delhi Government are advancing coordinated rehabilitation and social reintegration measures under the Bhiksha Vritti Mukt Delhi initiative.
- SMILE Coverage Expands Nationwide: The SMILE-Beggary Scheme operates across 216 cities in 33 States and Union Territories, supporting comprehensive rehabilitation and socio-economic empowerment.
- Hundred Cities Targeted Nationwide: The government aims to make 100 cities begging-free by 2031 through measurable indicators, digital monitoring and coordinated rehabilitation measures.

3. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य सेवाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चिकित्सकीय



प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क को प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए निर्देश जारी किया। यह परामर्श केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव द्वारा मुख्य सचिवों को भेजा गया। लागू नियमों के तहत, प्रतिष्ठानों को सेवाओं और सुविधाओं की दरें स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित करनी होंगी। इस उपाय का उद्देश्य मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता में सुधार करना, रोगियों को उपचार लागत का अनुमान लगाने में सक्षम बनाना, सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता करना, बिल संबंधी विवादों को कम करना और देश की व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास को मजबूत करना है।

मुख्य बिंदु:

- स्वास्थ्य सेवा मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि चिकित्सकीय प्रतिष्ठान स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के शुल्क को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
- द्विभाषी दर प्रदर्शन आवश्यक: लागू चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को रोगियों और परिचारकों के लिए सेवा दरों को स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।
- रोगी जागरूकता को प्राथमिकता: पारदर्शी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य परिवारों को उपचार व्यय का अनुमान लगाने, सोच-समझकर विकल्प चुनने और भ्रम तथा बिल संबंधी विवादों को कम करने में सहायता करना है।

Centre Directs States and Union Territories to Prominently Display Healthcare Service Rates at Clinical Establishments

The Union Ministry of Health and Family Welfare issued the directive urging all States and Union



Territories to ensure prominent display of healthcare service charges at clinical establishments. The advisory was communicated by Union Health Secretary Punya Salila Srivastava to Chief Secretaries. Under applicable rules, establishments must display rates for services and facilities in the local language and English. The measure seeks to improve pricing transparency, enable patients to estimate treatment costs, make informed decisions, reduce billing disputes and strengthen trust in healthcare delivery across the country's wider healthcare system.

Key Points:

- Healthcare Pricing Transparency: States and Union Territories have been directed to ensure clinical establishments prominently display charges for healthcare services and facilities.
- Bilingual Rate Display Required: Applicable clinical establishments must display service rates conspicuously in both the local language and English for patients and attendants.
- Patient Awareness Gets Priority: Transparent pricing is intended to help families estimate treatment expenditure, make informed choices and reduce confusion and billing disputes.

4. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित औषधि खोज को आगे बढ़ाने के लिए पेप्ट्रिस को 86 करोड़ रुपये की सहायता हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के माध्यम से बेंगलुरु स्थित पेप्ट्रिस टेक्नोलॉजीज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता- संचालित औषधि



खोज को आगे बढ़ाने के लिए 86 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। यह सहायता अनुसंधान विकास और नवाचार कोष के अंतर्गत दी गई है और 172 करोड़ रुपये मूल्य के विगोर कार्यक्रम का समर्थन करती है। परियोजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पहचाने गए चार औषधि उम्मीदवारों को पूर्व-नैदानिक विकास और सत्यापन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। इसका लक्ष्य इन उम्मीदवारों को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 4 से स्तर 6 तक ले जाना है, जिससे नैदानिक विकास के लिए उनकी तत्परता मजबूत हो सके और साथ ही स्वदेशी औषधीय अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और औषधि विकास क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सके।

मुख्य बिंदु:

- प्रमुख अनुसंधान वित्तीय सहायता: प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने अनुसंधान विकास और नवाचार कोष के अंतर्गत 86 करोड़ रुपये की सहायता के लिए बेंगलुरु स्थित पेप्ट्रिस टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- विगोर कार्यक्रम को मिला समर्थन: 172 करोड़ रुपये की विगोर परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा खोजे गए चार औषधि उम्मीदवारों को पूर्व-नैदानिक विकास और सत्यापन चरणों के माध्यम से आगे बढ़ाएगी।
- नैदानिक विकास मार्ग हुआ मजबूत: परियोजना का उद्देश्य नैदानिक परीक्षणों की तैयारी करते हुए चयनित औषधि उम्मीदवारों को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 4 से स्तर 6 तक आगे बढ़ाना है।

4. **TDB and DST Sign Agreement with Peptris for Rs 86 Crore Support to Advance AI-Driven Drug Discovery**

The Department of Science and Technology, through the Technology Development Board, extended Rs 86 crore support to Bengaluru-based Peptris Technologies for advancing AI-driven drug discovery. The assistance comes under the Research Development and Innovation Fund and supports the VIGOR programme, valued at Rs 172 crore. The project aims to advance four drug candidates identified using artificial intelligence through preclinical development and validation. It seeks to move these candidates from Technology Readiness Level 4 to Level 6, strengthening their readiness for clinical development while promoting indigenous pharmaceutical research, technological innovation and drug development capabilities.



Key Points:

- Major Research Funding Support: TDB signed an agreement with Bengaluru-based Peptris Technologies for Rs 86 crore support under the Research Development and Innovation Fund.
- VIGOR Programme Gains Support: The Rs 172 crore VIGOR project will advance four artificial intelligence-discovered drug candidates through preclinical development and validation stages.
- Clinical Development Pathway Strengthened: The project seeks to advance selected drug candidates from Technology Readiness Level 4 to Level 6 while preparing clinical trials.

5. रक्षा और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की उपस्थिति में भारतीय सेना ने जवानों के लिए भारत चावल की शुरुआत की

अक्टूबर 2026 में भारतीय सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी



की उपस्थिति में जवानों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले भारत चावल की शुरुआत की। इस पहल के तहत, देशभर में स्थित सेना के आपूर्ति डिपो तक चावल की सीधी आपूर्ति की जाएगी। इसमें लद्दाख और पूर्वोत्तर के दूरदराज के क्षेत्र भी शामिल हैं। इससे भारतीय खाद्य निगम की स्थानीय इकाइयों से चावल प्राप्त करने पर निर्भरता कम होगी। पाँच वर्ष के समझौते के तहत परिचालन संबंधी आपात परिस्थितियों में सेना भारतीय खाद्य निगम की भंडारण सुविधाओं, कर्मचारियों और सामग्री प्रबंधन से जुड़ी सुविधाओं का भी उपयोग कर सकेगी। इससे देशभर में रक्षा कर्मियों के लिए खाद्य आपूर्ति की विश्वसनीयता, रसद व्यवस्था की दक्षता और तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मुख्य बिंदु:

- भारत चावल पहल की शुरुआत: भारतीय सेना ने रक्षा कर्मियों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले भारत चावल की शुरुआत की है, जिसकी सीधी आपूर्ति देशभर में सेना के आपूर्ति डिपो तक की जाएगी।
- दूरदराज के क्षेत्रों तक आपूर्ति: लद्दाख और पूर्वोत्तर में सेना के दूरस्थ ठिकानों तक चावल की सीधी आपूर्ति की जाएगी, जिससे भारतीय खाद्य निगम की स्थानीय इकाइयों से चावल प्राप्त करने पर निर्भरता कम होगी।
- सैन्य रसद साझेदारी मजबूत: पाँच वर्ष के समझौते के तहत परिचालन संबंधी आपात परिस्थितियों में सेना भारतीय खाद्य निगम की भंडारण सुविधाओं, कर्मचारियों और सामग्री प्रबंधन संसाधनों का उपयोग कर सकेगी।

Indian Army Introduces Bharat Rice for Troops in Presence of Defence and Consumer Affairs Ministers

In October 2026, the Indian Army introduced superior-quality Bharat Rice for troops in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi. Under the initiative, rice will be delivered directly to Army Supply Depots across India, including remote locations in Ladakh and the Northeast, reducing dependence on collection from local Food Corporation of India facilities. A five-year agreement also allows the Army to utilise FCI warehousing, manpower and material-handling infrastructure during operational contingencies, strengthening food supply reliability, logistical efficiency and preparedness for defence personnel nationwide.



Key Points:

- Bharat Rice Initiative Launched: The Indian Army introduced superior-quality Bharat Rice for defence personnel, with direct deliveries planned to Army Supply Depots nationwide.
- Remote Areas Receive Supplies: Direct deliveries will cover distant Army locations in Ladakh and the Northeast, reducing dependence on collection from local FCI facilities.
- Military Logistics Partnership Strengthened: A five-year agreement enables the Army to use FCI warehousing, manpower and material-handling resources during operational contingencies.

6. रक्षा मंत्री ने 2026 एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 27 पदक

जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया

20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आइची- नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक



किया गया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रक्षा बलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तीनों सेनाओं के 92 खिलाड़ियों ने 19 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और छह स्वर्ण, ग्यारह रजत तथा दस कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। उनके प्रदर्शन ने भारत के कुल 85 पदकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल थे। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जो राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों में सेना के खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु:

- सेना के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड प्रदर्शन: रक्षा बलों के खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण, ग्यारह रजत और दस कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर एशियाई खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
- तीनों सेनाओं की मजबूत भागीदारी: जापान में आयोजित 2026 एशियाई खेलों में तीनों सेनाओं के 92 खिलाड़ियों ने 19 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया।
- भारत चौथे स्थान पर रहा: सेना के खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान से भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा।

6. Defence Minister Felicitates Services Athletes for Winning Record 27 Medals at 2026 Asian Games

The 20th Asian Games were held in Aichi-Nagoya, Japan, from 19 September to 4 October 2026. Defence



Minister Rajnath Singh later felicitated Defence Forces athletes for achieving their best-ever Asian Games performance. Ninety-two athletes from the three Services competed across 19 disciplines and secured 27 medals, including six gold, eleven silver and ten bronze. Their performance contributed significantly to India's tally of 85 medals, comprising 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India finished fourth in the medal standings, highlighting the strong contribution of Services sportspersons to national sporting excellence.

Key Points:

- Services Achieve Record Haul: Defence forces athletes secured their best-ever Asian Games performance with 27 medals, comprising six gold, eleven silver and ten bronze.
- Strong Services Representation: Ninety-two athletes from the three Services competed across 19 disciplines at the 2026 Asian Games held in Japan.
- India Finishes Fourth Overall: Services athletes contributed substantially as India finished fourth with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze.

7. पीएम-सेतु के तहत सूरत और विशाखापत्तनम समूहों के लिए शेयरधारक समझौतों पर हस्ताक्षर, नौ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 440 करोड़ रुपये मंजूर

✎ पीएम- सेतु के तहत सूरत और विशाखापत्तनम समूहों के लिए शेयरधारक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें आर्सेलरमिस्तल निप्पॉन



स्टील इंडिया को उद्योग भागीदार बनाया गया है। इस पहल के तहत दोनों प्रमुख एवं संबद्ध केंद्रों वाले समूहों में नौ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए लगभग 440 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। पीएम-सेतु का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू करने और उद्योगों के साथ साझेदारी मजबूत करने के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण संस्थानों में बदलना है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार क्षमता और प्रशिक्षुता के अवसरों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। साथ ही, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बदलती तकनीकी आवश्यकताओं और कार्यबल की जरूरतों के अनुरूप हो।

मुख्य बिंदु:

- उद्योगों के साथ साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया: पीएम-सेतु के तहत सूरत और विशाखापत्तनम समूहों के लिए शेयरधारक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें आर्सेलरमिस्तल निप्पॉन स्टील इंडिया उद्योग भागीदार है।
- नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का होगा उन्नयन: सूरत और विशाखापत्तनम के प्रमुख एवं संबद्ध केंद्रों वाले समूहों में नौ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 440 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण का विस्तार: पीएम-सेतु का उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढाँचे, उद्योग साझेदारी, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम और रोजगार-केंद्रित व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करना है।

7. PM-SETU Shareholders' Agreements Signed for Surat and Visakhapatnam Clusters, Rs 440 Crore Approved to Upgrade Nine Government ITIs

✎ Shareholders' Agreements

under PM-SETU were signed for the Surat and Visakhapatnam clusters, with ArcelorMittal Nippon



Steel India serving as the industry partner. The initiative involves an approved investment of around Rs 440 crore for upgrading nine Government Industrial Training Institutes across the two hub-and-spoke clusters. PM-SETU aims to transform ITIs into industry-aligned training institutions by modernising infrastructure, introducing future-ready curricula and strengthening partnerships with industry. The programme focuses on improving training quality, employability and apprenticeship opportunities while ensuring that vocational education responds effectively to evolving technological requirements and workforce needs across major industrial sectors.

Key Points:

- Industry Partnerships Formalised: Shareholders' Agreements were signed for Surat and Visakhapatnam clusters under PM-SETU with ArcelorMittal Nippon Steel India as industry partner.
- Nine ITIs Receive Upgrades: Around Rs 440 crore has been approved for modernising nine Government ITIs across the Surat and Visakhapatnam hub-and-spoke clusters.
- Industry Aligned Training Expanded: PM-SETU seeks to modernise Government ITIs through upgraded infrastructure, industry partnerships, future-ready curricula and stronger employment-oriented vocational training.

8. सीएपीएसएस और भारतीय वायु सेना ने अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया

✎ एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज केंद्र यानी सीएपीएसएस और भारतीय वायु सेना ने अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के साथ 9 अक्टूबर 2026 को



नई दिल्ली के सुब्रतो पार्क में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में बदलते युद्धक्षेत्र में वायु शक्ति की केंद्रीय भूमिका पर चर्चा की गई और इसमें सहयोगी देशों की वायु सेनाओं, सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा में अभ्यास से प्राप्त परिचालन अनुभवों के आधार पर युद्ध की उभरती चुनौतियों, सैन्य सिद्धांतों से जुड़ी प्राथमिकताओं और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया। 2001 में स्थापित सीएपीएसएस एक स्वायत्त अनुसंधान संस्था है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु और एयरोस्पेस से जुड़े विषयों पर अध्ययन करती है।

मुख्य बिंदु:

- वायु शक्ति पर संगोष्ठी आयोजित: सीएपीएसएस और भारतीय वायु सेना ने अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के साथ 9 अक्टूबर को सुब्रतो पार्क में एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
- बदलते युद्धक्षेत्र पर चर्चा: संगोष्ठी में बदलती युद्ध परिस्थितियों के बीच वायु शक्ति की केंद्रीय भूमिका पर विचार किया गया, जिसमें सहयोगी देशों की वायु सेनाओं और सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
- भविष्य के सहयोग पर जोर: उड़ान अभ्यास से प्राप्त परिचालन अनुभवों के आधार पर सैन्य सिद्धांतों से जुड़ी प्राथमिकताओं और भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान पर चर्चा की गई।

8. CAPSS and Indian Air Force Organise Seminar Under Exercise Tarang Shakti 2026

✎ The Centre for Aerospace Power and Strategic Studies, or CAPSS, and the Indian Air Force organised



a seminar on 9 October 2026 at Subroto Park, New Delhi, alongside Exercise Tarang Shakti 2026. The seminar focused on the central role of air power in the evolving battlespace and brought together partner air forces, military leaders and experts. Discussions drew upon operational experiences from the exercise to examine emerging warfare challenges, identify doctrinal priorities and explore future cooperation. Established in 2001, CAPSS is an autonomous research body focusing on national security, nuclear and aerospace issues.

Key Points:

- Air Power Seminar Conducted: CAPSS and Indian Air Force organised a seminar on 9 October at Subroto Park alongside Exercise Tarang Shakti 2026.
- Evolving Battlespace Discussed: The seminar examined the central role of air power amid changing warfare, bringing together partner air forces and military leaders.
- Future Cooperation Takes Focus: Discussions used operational experiences from the flying exercise to identify doctrinal priorities and potential areas for cooperation among participating air forces.

9. अक्टूबर 2026 में आपूर्ति में सुधार के बीच बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 18 मिलियन टन से अधिक

रहा

कोयला मंत्रालय के अनुसार, घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 29 सितंबर 2026 से



लगातार 18 मिलियन टन से अधिक बना रहा। 29 सितंबर को भंडार 18.932 मिलियन टन था, जो 10 अक्टूबर को 18.205 मिलियन टन रहा। आपूर्ति में सुधार के कारण अक्टूबर के दौरान कोयला भंडार में कमी की रफ्तार काफी धीमी हुई। बिजली क्षेत्र को कोयले की औसत आपूर्ति सितंबर के 2.21 मिलियन टन प्रतिदिन से बढ़कर 2.49 मिलियन टन प्रतिदिन हो गई। रेलवे रैक की औसत दैनिक लोडिंग बढ़कर 469 रैक होने से भी कोयले की दुलाई बेहतर हुई और निर्बाध बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिली।

मुख्य बिंदु:

- कोयला भंडार स्थिर रहा: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 29 सितंबर से 18 मिलियन टन से अधिक बना रहा और 10 अक्टूबर को यह 18.205 मिलियन टन दर्ज किया गया।
- कोयला आपूर्ति में सुधार: अक्टूबर की शुरुआत में कोयले की औसत दैनिक आपूर्ति सितंबर में दर्ज 2.21 मिलियन टन से बढ़कर 2.49 मिलियन टन हो गई।
- रेलवे परिवहन से आपूर्ति को बढ़ावा: औसत रैक लोडिंग सितंबर के 426 रैक प्रतिदिन से बढ़कर अक्टूबर के पहले दस दिनों में 469 रैक प्रतिदिन हो गई, जिससे कोयले की उपलब्धता बेहतर हुई।

9. Coal Stocks at Power Plants Remain Above 18 Million Tonnes as Supplies Improve in October 2026

According to the Ministry of Coal, coal stocks at domestic coal-based power plants remained stable above 18 million tonnes



from 29 September 2026. Stocks stood at 18.932 million tonnes on 29 September and 18.205 million tonnes on 10 October. Improved supplies helped slow inventory depletion significantly during October. Average coal supply to the power sector increased to 2.49 million tonnes per day, compared with 2.21 million tonnes in September. Higher railway rake loading, averaging 469 rakes daily, also strengthened coal movement and supported adequate supplies for uninterrupted electricity generation.

Key Points:

- Coal Inventories Remain Stable: Stocks at domestic coal-based power plants remained above 18 million tonnes from 29 September, reaching 18.205 million tonnes on 10 October.
- Supply Pace Shows Improvement: Average daily coal supply rose to 2.49 million tonnes during early October from 2.21 million tonnes recorded in September.
- Railway Movement Supports Supply: Average rake loading increased from 426 per day in September to 469 during October's first ten days, improving coal availability.

10. नशा मुक्त युवा अभियान के तहत 1,469 स्थानों पर युवा संसद और युवा मेलों का आयोजन

✎ माई भारत ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत 10 अक्टूबर 2026 को 34 राज्यों में 1,469 स्थानों पर पड़ोस युवा संसद



और युवा मेलों का आयोजन किया। इस राष्ट्रव्यापी पहल में 3.65 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। प्रखंड स्तर पर आयोजित युवा संसदों में नशीले पदार्थों के सेवन, उसके सामाजिक दुष्परिणामों और इसकी रोकथाम के प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने प्रेरक अनुभव भी साझा किए और समुदाय आधारित प्रयासों को बढ़ावा दिया। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त समुदायों के निर्माण के लिए प्रेरित करना, जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करना और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु:

- देशभर में युवा अभियान का आयोजन: माई भारत ने 10 अक्टूबर 2026 को 34 राज्यों के 1,469 स्थानों पर पड़ोस युवा संसद और युवा मेलों का आयोजन किया।
- बड़े पैमाने पर भागीदारी: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आयोजित गतिविधियों में 3.65 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया।
- नशे की रोकथाम के प्रति जागरूकता: प्रखंड स्तर की युवा संसदों में नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी चुनौतियों, रोकथाम के उपायों और प्रेरक अनुभवों पर चर्चा की गई, ताकि युवाओं को नशा मुक्त समुदाय बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

— ★ ★ ★ —

10. MY Bharat Conducts Youth Parliaments and Yuva Melas at 1,469 Locations Under Nasha Mukta Yuva Campaign

✎ MY Bharat organised Neighbourhood Youth Parliaments and Yuva Melas at 1,469 locations across 34 States on 10 October 2026 under the Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Abhiyan. More than 3.65 lakh youth and citizens participated in the nationwide initiative. Conducted at the block level, Youth Parliaments encouraged discussions on substance abuse, its social consequences and effective prevention strategies. Participants also shared inspiring experiences and promoted community-based action. The campaign seeks to empower young people as advocates for drug-free communities while encouraging responsible citizenship and their participation in building a developed India.



Key Points:

- Nationwide Youth Campaign Conducted: MY Bharat organised Neighbourhood Youth Parliaments and Yuva Melas across 1,469 locations in 34 States on 10 October 2026.
- Mass Participation Recorded Nationwide: More than 3.65 lakh youth and citizens participated in activities conducted under the Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Abhiyan.
- Drug Prevention Awareness Strengthened: Block-level Youth Parliaments discussed substance-abuse challenges, prevention strategies and inspiring experiences to encourage young people to advocate drug-free communities.

— ★ ★ ★ —

दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. अक्टूबर 2026 में माई भारत ने किस अभियान के तहत 1,469 स्थानों पर पड़ोस युवा संसद और युवा मेलों का आयोजन किया ?

- (a) फिट इंडिया युवा अभियान
- (b) विकसित भारत के लिए युवा शक्ति अभियान
- (c) विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान
- (d) विकसित युवा समर्थ भारत अभियान

Q2. कोयला मंत्रालय के अनुसार, 29 सितंबर 2026 से घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार किस स्तर से ऊपर स्थिर बना रहा ?

- (a) 12 मिलियन टन
- (b) 15 मिलियन टन
- (c) 18 मिलियन टन
- (d) 21 मिलियन टन

Q3. अक्टूबर 2026 में भारतीय वायु सेना के साथ रक्षा संगोष्ठी का सह-आयोजन करने वाले 'सीएपीएसएस' का पूरा नाम क्या है ?

- (a) एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज केंद्र
- (b) एयर पावर स्टडीज केंद्र
- (c) एयरोस्पेस प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी सिस्टम्स गठबंधन
- (d) एयर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी स्टडीज परिषद

Q4. अक्टूबर 2026 में पीएम-सेतु के तहत किन दो प्रमुख औद्योगिक समूहों के लिए शेयरधारक समझौतों को अंतिम रूप दिया गया ?

- (a) सूरत और विशाखापत्तनम
- (b) पुणे और चेन्नई
- (c) अहमदाबाद और कोच्चि
- (d) बेंगलुरु और कानपुर

Q5. 20वें एशियाई खेल 2026 की मेजबानी किस शहर और देश ने की, जहाँ भारतीय रक्षा सेवाओं के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 27 पदक जीते ?

- (a) हांगझोऊ, चीन
- (b) रियाद, सऊदी अरब
- (c) दोहा, कतर
- (d) आइची-नागोया, जापान

Q1. In October 2026, MY Bharat organised Neighbourhood Youth Parliaments and Yuva Melas at 1,469 locations under which campaign?

- (a) Fit India Youth Campaign
- (b) Yuva Shakti for Viksit Bharat Abhiyan
- (c) Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Abhiyan
- (d) Viksit Yuva Samarth Bharat Abhiyan

Q2. According to the Ministry of Coal, coal stocks at domestic coal-based power plants remained stable above what level since September 29, 2026?

- (a) 12 million tonnes
- (b) 15 million tonnes
- (c) 18 million tonnes
- (d) 21 million tonnes

Q3. What does the acronym 'CAPSS' stand for, which co-organized the defense seminar with the Indian Air Force in October 2026?

- (a) Centre for Aerospace Power and Strategic Studies
- (b) Centre for Air Power Studies
- (c) Coalition for Aerospace Protection and Safety Systems
- (d) Council for Air Strategy and Policy Studies

Q4. Shareholders' agreements under PM-SETU signed in October 2026 were finalized for which two major industrial clusters?

- (a) Surat and Visakhapatnam
- (b) Pune and Chennai
- (c) Ahmedabad and Kochi
- (d) Bengaluru and Kanpur

Q5. Which city and country hosted the 20th Asian Games in 2026, where Indian Services athletes won a record 27 medals?

- (a) Hangzhou, China
- (b) Riyadh, Saudi Arabia
- (c) Doha, Qatar
- (d) Aichi-Nagoya, Japan

Q6. अक्टूबर 2026 में सेना के लिए भारत चावल की शुरुआत रक्षा मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री की उपस्थिति में की गई। वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री का पद किसके पास है?

- (a) प्रह्लाद जोशी (b) राजनाथ सिंह
(c) शिवराज सिंह चौहान (d) पीयूष गोयल

Q7. अक्टूबर 2026 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पेप्ट्रिस को प्रदान की गई सहायता विशेष रूप से किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लक्षित है?

- (a) क्वांटम कूटलेखन
(b) कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित औषधि खोज
(c) स्वायत्त उपग्रह नौवहन
(d) गहरे समुद्र में खनिज खनन

Q8. अक्टूबर 2026 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों और चिकित्सालयों में दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य करने वाला राष्ट्रीय निर्देश किस प्राधिकरण ने जारी किया?

- (a) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
(b) नीति आयोग
(c) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(d) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

Q9. भारत सरकार की 'भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत' पहल, जो हाल ही में 2031 तक 100 शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य को लेकर चर्चा में रही, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत लागू की जा रही है?

- (a) पीएम-दक्ष (b) स्माइल
(c) नमस्ते (d) पीएम-अजय

Q10. पीएम गतिशक्ति, जिसने अक्टूबर 2026 में 5 वर्ष पूरे किए, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है?

- (a) ग्रामीण आवास के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण
(b) एकीकृत अवसंरचना योजना और बहुविध संपर्क
(c) माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता
(d) राष्ट्रीय राजमार्गों का निजीकरण

Q6. In October 2026, the introduction of Bharat Rice for the Army took place in the presence of the Defence Minister and Consumer Affairs Minister. Who currently holds the portfolio of Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution?

- (a) Prahlad Joshi
(b) Rajnath Singh
(c) Shivraj Singh Chouhan
(d) Piyush Goyal

Q7. The support granted to Peptris by the Department of Science and Technology (DST) in October 2026 is specifically targeted at advancing which technology domain?

- (a) Quantum Cryptography
(b) AI-Driven Drug Discovery
(c) Autonomous Satellite Navigation
(d) Deep-Sea Mineral Mining

Q8. Which authority issued the national directive in October 2026 mandating rates to be displayed at hospitals and clinics across all States and UTs?

- (a) Indian Council of Medical Research (ICMR)
(b) NITI Aayog
(c) Ministry of Health and Family Welfare
(d) National Medical Commission (NMC)

Q9. The Government of India's 'Bhiksha Vritti Mukh Bharat' initiative, recently in the news for its target of making 100 cities begging-free by 2031, is being implemented under which of the following schemes?

- (a) PM-DAKSH
(b) SMILE
(c) NAMASTE
(d) PM-AJAY

Q10. PM GatiShakti, which completed 5 years in October 2026, primarily aims to achieve which of the following objectives?

- (a) Direct cash transfer for rural housing
(b) Integrated infrastructure planning and multimodal connectivity
(c) Digital literacy in secondary schools
(d) Privatization of national highways

उत्तरमाला (Answer Key)

1 C 2 C 3 A 4 A 5 D 6 A 7 B 8 C 9 B 10 B

